कांग्रेस 70 से अधिक सीटें जीतेगी; सीएम हिमंत को बताया देश में सबसे भ्रष्ट- खरगे

ASHOKA

SMA - Ashoka Express Publication

अशोका एक्सप्रेस

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती

प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्षः 29 ● अंक : 13 ● नई दिल्ली ● 09 से 15 अप्रैल 2026 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

पाताल से ढूंढ़ निकालेंगे, राहुल तक जाएगा केस- हिमंत की पवन खेड़ा को चुनौती, पत्नी पर आरोपों से भड़के सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर आ गई है। मुख्यमंत्री सरमा ने अपनी पत्नी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर पवन खेड़ा को दो टूक चेतावनी दी है।

सरमा ने कहा कि अगर खेड़ा पाताल में भी जाकर छिप जाते हैं, तो असम पुलिस उन्हें वहां से भी ढूंढ कर लाएगी। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के खिलाफ कुछ दस्तावेज भी पेश किए। मुख्यमंत्री का दावा है कि खेड़ा ने यह सब कांग्रेस नेता राहुल गांधी

के इशारे पर किया है। सरमा ने कहा कि पवन खेड़ा ने जो कागज पेश किए हैं, वे केवल राजनीति से प्रेरित हैं और इसके पीछे की असली पटकथा राहुल गांधी ने लिखी है।

असम पुलिस की दिल्ली में दस्तक

मुख्यमंत्री की चेतावनी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। मंगलवार यानी 7 अप्रैल को असम पुलिस की एक टीम अचानक पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गई। पुलिस की इस कार्रवाई ने असम से लेकर दिल्ली तक, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सरमा ने कहा कि पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा, यानी, पाताल से भी ढूंढ़ निकालेंगे। इस बयान से साफ है कि असम सरकार इस मामले में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री सरमा ने केवल पवन खेड़ा पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि सीधे तौर पर राहुल गांधी को भी इस मामले में घसीटा है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ेगा और आने वाले समय में राहुल गांधी से भी इस संबंध में कड़ी पूछताछ की जा सकती है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी अब अपने चरम पर है।

जहां एक तरफ कांग्रेस इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रही है, वहीं मुख्यमंत्री सरमा ने इसे अपनी निजी और पारिवारिक प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए आर-पार की लड़ाई का एलान कर दिया है।

जयराम रमेश, बोले- हिमंता बिस्वा परेशान और डरे हुए हैं

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें परेशान, हताश और डरा हुआ बताया। यह घटना तब हुई जब असम पुलिस की एक टीम ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास का दौरा किया। पुलिस की यह कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल पासपोर्ट विवाद से संबंधित है, जो मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की एफआईआर के बाद सामने आया है। एक्स से बात करते हुए रमेश ने निजामुद्दीन पूर्व स्थित खेड़ा के घर के बाहर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की निंदा की और इसे चुड़ैल का शिकार और दंभिक द्वारा राज्य मशीनरी का उपयोग करके विपक्ष की उन आवाजों को दबाने का प्रयास बताया जो कथित कुकर्मों को उजागर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और भयभीत हैं। यह कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जिसमें एक तानाशाह विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। जो लोग डराते-धमकाते हैं, वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी असम पुलिस की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री सरमा से आग्रह किया कि वे धमकियों और अपशब्दों का सहारा लेने के बजाय खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों का समाधान करें। उन्होंने कहा कि सरमा के खिलाफ लगाए गए आरोप गवाहों और सबूतों से समर्थित हैं और उनका उचित समाधान किया जाना चाहिए।

प. बंगाल- मतदाताओं में बेचैनी

पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है लेकिन लाखों मतदाता अनिश्चितता की स्थिति में हैं और चिंतित हैं। अत्यधिक लंबी सत्यापन प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार से वंचित होने का खतरा है क्योंकि यह प्रक्रिया बहिष्कार का रूप ले चुकी है। मतदाता सूची से हटाए गए 6 लाख मतदाताओं के नाम विचाराधीन श्रेणी में डाले गए थे। इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि विचाराधीन प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। पूरी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मालदा में प्रदर्शनकारी मतदाताओं द्वारा एसआईआर अधिकारियों का घेराव और उन्हें कई घंटों तक बंधक बनाए जाने की घटना के पीछे राजनीतिक सुनियोजित घटनाक्रम के तार राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो (एनआईए) ढूंढ रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सख्त रवैया अपनाते हुए पश्चिम बंगाल प्रशासन को खूब खरी-खोटी सुनाई थी लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया अब बहिष्कार में तब्दील हो गई है। क्योंकि लोग लंबी प्रक्रिया में घंटों इंतजार करने की बजाय घर में ही बैठक पसंद कर रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की अर्जी सुनने के लिए गठित न्यायाधिकरणों ने अभी काम भी शुरू नहीं किया है और एसआईआर में हुई गड़बड़ियों के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार मोहताब शेख को वोट डालने का मौका मिल गया है। मोहताब शेख का नाम 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के विचाराधीन मामले के कालम में डाल दिया गया था। एक न्यायधिकरण ने उनका नाम बहाल कर दिया। मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाने के कारण मोहताब शेख नामांकन भी दाखिल नहीं कर सके थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम ने शेख के मामले की सुनवाई के लिए साल्ट लेक में एक विशेष सुनवाई आयोजित की। इस दौरान शेख ने अपना-पासपोर्ट प्रस्तुत किया। यह वही दस्तावेज था जो उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया था। न्यायमूर्ति शिवज्ञानम ने सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच की और अपने आदेश में कहा कि निर्वाचन आयोग ने न्यायिक अधिकारी द्वारा निर्णय के दौरान उनका नाम हटाए जाने से संबंधित परिस्थितियों को प्रस्तुत न करने के लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया था।

न्यायमूर्ति शिवज्ञानम ने अंततः यह माना कि शेख द्वारा दिया गया पासपोर्ट पर्याप्त था और चुनाव आयोग को रविवार रात 8 बजे तक एक अतिरिक्त सूची के माध्यम से उन्हें मुर्शिदाबाद का वैध मतदाता घोषित करने का आदेश दिया। निर्वाचन आयोग ने 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी जिसमें लाखों मतदाताओं को विचाराधीन के रूप में चिह्नित किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं और गड़बड़ियों का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 326 में निहित संवैधानिक वादा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता बनने का अधिकार होगा, पूरा नहीं होगा। क्या गड़बड़ियों वाली मतदाता सूची से निष्पक्ष और ईमानदार चुनावों की उम्मीद की जा सकती है? चुनाव आयोग की विश्वसनियता लगातर प्रभावित हो रही है और जनता के बीच इसका भरोसा काफी कम हो चुका है। चुनाव आयोग, जिसका प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने और मतदाता समावेशन को प्राथमिकता देने का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे इन गंभीर चिंताओं का समाधान अवश्य करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय, जिसने पिछले वर्ष बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के दौरान हस्तक्षेप करके प्रक्रिया को मतदाताओं की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में मदद की थी, उसे पश्चिम बंगाल पर भी नजर रखनी चाहिए। शुरुआत से ही, बंगाल में किया गया विशेष गहन संशोधन अन्य राज्यों की तुलना में अधिक जटिल प्रतीत होता है। समय की कमी के बीच कई विवादास्पद नए प्रावधान लागू किए गए। फरवरी में न्यायालय ने एसआईआर को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करते हुए लगभग 500 न्यायिक अधिकारियों को लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए थे। अब क्योंकि चुनाव सिर पर है और प्रक्रिया अधूरी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया काफी विवादित रही है। 28 फरवरी को जारी की गई राज्य की अंतिम वोटर लिस्ट में 6.44 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे। इस प्रक्रिया के तहत करीब 63 लाख 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट' मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। वहीं करीब 60 लाख मतदाताओं की स्थिति 'जांच के अधीन' बनी रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद करीब 700 न्यायिक अधिकारियों को 'जांच के अधीन' मौजूद वोटरों के रिकॉर्ड की जांच करने और उनकी मतदान पात्रता तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब तक 52 लाख से ज़्यादा 'जांच के अधीन' रखे गए मामलों का निपटारा किया जा चुका है, लेकिन इस प्रक्रिया में हटाए गए मतदाताओं की सही संख्या अभी भी पता नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या लाखों मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। कोलकाता स्थित थिंकटैंक 'सबर इंस्टीट्यूट' के एक विश्लेषण के अनुसार, पहले और दूसरे चरण में न्यायिक अधिकारियों ने जिन वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया है उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं का है। एसआईआर प्रक्रिया के कारण मतदाताओं में बेबसी की भावना पैदा हुई। उनकी उदासीनता मतदाता के तौर पर अधिकार को लेकर चिंताओं का ही एक रूप है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल के मतदाताओं की चिंता दूर कैसे की जाए।

सम्पादकीय

मरघट के चौकीदारों की नकेल कसिए !

अमेरिका-इजराइल और ईरान की जंग शुरू होने के बाद जैसे ही एलपीजी गैस की कमी की आशंका पैदा हुई थी, तब मैंने लिखा था कि ढाबों को गैस सिलेंडर मिलता रहे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खासकर ट्रक ड्राइवरों के लिए तो भोजन का एकमात्र माध्यम ये ढाबे ही होते हैं। आशंका सच साबित हुई है। बहुत से ढाबे तो बंद हो चुके हैं। जो खुले हैं, वे लकड़ियां जला रहे हैं और एक बार जो खाना बना लिया, वही दिन भर परोस रहे हैं। कई जगह तो खाना मिल भी नहीं रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी कई होटल और रेस्तरां इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। कामकाजी महिलाएं परेशान हैं कि काम पर जाएं या सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़ी रहें। सरकार कहती है कि सिलेंडर की कोई कमी बिल्कुल नहीं है, मगर सप्लाई चेन में जरूर दिक्कतें आ रही हैं। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात होर्मुज जलडमरूमध्य से करता है। एलपीजी लदे जहाज पहले 11 दिनों में होर्मुज से भारत पहुंच जाया करते थे। इस रास्ते से ईरान की सदाशयता के कारण जहाज अभी भी आ रहे हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम है और समय ज्यादा लग रहा है। दूसरे देशों से भी एलपीजी लदे जहाज आ रहे हैं, लेकिन वो रास्ते बहुत लंबे हैं। देश से एलपीजी मिलने की समस्या के कारण सरकार ने यह तय किया कि पहले घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता में नहीं है। नतीजतन शहरी क्षेत्र के कई होटलों और रेस्तरां में घरेलू गैस का उपयोग होने लगा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यावसायिक एलपीजी के साथ घरेलू एलपीजी की भी धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इस कालाबाजारी की चर्चा से पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कर लीजिए। भारत में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या करीब 33 करोड़ है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन 55 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की मांग रहती है। अब यह बढ़कर 75 लाख सिलेंडर प्रतिदिन हो गई है, सवाल लाजमी है कि 20 लाख सिलेंडर प्रतिदिन कहां जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब इतने सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है तो फिर कालाबाजारी क्यों? क्या ये केवल पैनिक बुकिंग का नतीजा है? या फिर मरघट के चौकीदार सक्रिय हो गए हैं जो संकट के वक्त भी केवल अपने मुनाफे की बात ही सोचते हैं! आज आप बुकिंग कराएं तो सिलेंडर भले ही न मिले लेकिन कालाबाजार में दोगुनी कीमत पर आपको बड़ी सहजता से सिलेंडर मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि कालाबाजारी का ये पैसा आम आदमी की जेब से लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भारत में पेट्रोलियम कंपनियां सौ फीसदी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और एलपीजी की कमी को लेकर लोग आशंकित न हों लेकिन हालात ये हैं कि लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रेगुलर इंडक्शन और इम्प्रूव्ड इंडक्शन चूल्हे खरीदने शुरू किए तो उनकी कीमतें आसमान छूने लगीं, वहां भी मरघट के चौकीदारों ने अपना खेल दिखा दिया, जो इंडक्शन दो हजार रुपए का मिल रहा था, वह अभी चार से साढ़े चार हजार रुपए का मिल रहा है। क्या किसी ने भी इस बात पर गौर करने की कोशिश की कि इंडक्शन की कीमतें किसने बढ़ा दीं? इस कालाबाजारी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या कंपनियों से या फिर डीलर्स से पूछा गया कि कीमतें क्यों बढ़ीं? बिल्कुल नहीं पूछा, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहां है ही नहीं जो ऐसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई करे। हमारे यहां पेट्रोल और डीजल को लेकर भी हाहाकार मच चुका होता लेकिन सरकारी दक्षता के कारण हालात नहीं बिगड़े, पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में देश के कई हिस्सों में डीजल न मिल पाने की अफवाह उड़ी।

बंगाल में लाखों लोग वोट नहीं डाल पाएंगे!

भारत में राज्यपाल बनने के बाद सक्रिय राजनीति में लौटना कोई अनोखी बात नहीं है। कई नेता राज्यपाल रहने के बाद सक्रिय राजनीति में लौटे और मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बने हैं। सुशील कुमार शिंदे से लेकर मोतीलाल वोरा तक की मिसालें हैं। भाजपा ने भी उत्तर प्रदेश में बेबीरानी मौर्य से लेकर तमिलनाडु में तमिलिसाई सौंदर्यराजन तक को चुनाव लड़ाया। लेकिन अगर भाजपा का कोई नेता बुजुर्ग हो और राज्यपाल रहा हो फिर भी उसे चुनाव लड़ने का मौका मिले तो यह भाजपा के कई बुजुर्ग नेताओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी। असल में भाजपा ने एक अघोषित नियम बना रखा है कि 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अपवाद बनाया गया है। लेकिन इस बार भाजपा केरल में पूर्व राज्यपाल के.राजशेखरन को चुनाव लड़ा रही है, जिनकी उम्र 73 साल है। गौरतलब है कि कुम्मनम राजशेखरन मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। वे इस बार अरानमुला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक समय दक्षिण भारत और खास कर केरल की राजनीति में वे भाजपा का चेहरा माने जाते थे। लंबे समय तक संघ प्रचारक और भाजपा के नेता रहे राजशेखरन की कुल संपत्ति एक लाख रुपए की है।

ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार लाखों लोग विधानसभा चुनाव में वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। इसका कारण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में हुई देरी है। असल में किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम ज्यादा जटिल हो गया।

चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों के मुकाबले तार्किक विसंगति का मुद्दा बंगाल में ज्यादा उठाया और लाखों मतदाताओं के दस्तावेज की कई-कई बार जांच हुई। एक बार और अभी ट्रिब्यूनल में जांच होनी है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार लाखों लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। हालांकि यह सवाल अपनी जगह है कि क्या लाखों लोगों को वोट डालने से वंचित करके चुनाव कराया जा सकता है? इस मामले में हर जगह सुप्रीम कोर्ट शामिल है और सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाजा है कि लोगों के नाम कटेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके बावजूद चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। इसका एक संकेत सुप्रीम कोर्ट की पिछले बुधवार की टिप्पणी से भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की वजह से एक चुनाव में किसी मतदाता का नाम कट जाने का यह मतलब नहीं है कि उसका नाम हमेशा के लिए कट गया। जाहिर है कि नाम कटने के बाद भी चुनाव की प्रक्रिया तय शिड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ेगी। इससे सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग जान-बूझ कर किसी खास मकसद से लाखों लोगों को वोट डालने से वंचित रखेगा?

पुडुचेरी में अगर हारी तो कांग्रेस खुद ज़िम्मेदार

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए सबसे आदर्श स्थिति दक्षिणी राज्यों में है। चुनाव सर्वेक्षणों में बताया जा रहा है कि कांग्रेस केरल में चुनाव जीत सकती है। तमिलनाडु में भी डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन वापस सत्ता हासिल कर सकता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मामला उलझा हुआ है। 30 विधानसभा सीटों वाले राज्य पुडुचेरी में 2016 में कांग्रेस जीती थी और अहमद पटेल के करीबी रहे वी नारायणसामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन 2021 के चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी और कांग्रेस के कारण डीएमके भी हारी। इस बार भी अगर पुडुचेरी में एनडीए चुनाव जीतता है तो उसका कारण कांग्रेस पार्टी होगी। पुडुचेरी में कांग्रेस के लिए माहौल ठीक नहीं है। इसके बावजूद जैसे पिछली बार कांग्रेस ने जिद करके ज्यादा सीटें ली और गठबंधन को हरवाया उसी तरह इस बार भी वह ज्यादा सीटें लेकर लड़ रही है। गौरतलब है कि 2021 में कांग्रेस 14 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ दो सीट जीत पाई। दूसरी ओर डीएमके 13 सीटों पर लड़ कर छह पर जीती। इससे पहले 2016 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थीं। नारायणसामी ने कांग्रेस को 17 से दो सीट पर ला दिया। इस बार भी कांग्रेस ने जिद करके 16 सीटें ली है और डीएमके को पहले की तरह 13 सीटें दी हैं। यही नहीं, बाद में कांग्रेस ने पांच और सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए। इसीलिए अगर इस बार भी गठबंधन हारता है तो जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी।

सीसीटीवी लगाओ, उतारो और फिर लगाओ

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुरक्षा और खास कर महिला सुरक्षा का हवाला देकर लाखों सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। अब रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार कह रही है कि ये चाइनीज कंपनी के सीसीटीवी कैमरे हैं, इसलिए उनको हटाया जाएगा। यह काम शुरू भी हो गया है। एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे उतारे जा रहे हैं। इन कैमरों को लगाने का काम 2020 में शुरू हुआ था और 2022 के अंत तक यह काम चला था। अब इतनी जल्दी इनको हटाया जा रहा है। इनकी जगह नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वैसे पूरी दिल्ली में कुल दो लाख 74 हजार से कुछ ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो बहुत कम हैं। बहरहाल, भाजपा सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दिल्ली में लगे एक लाख 40 हजार कैमरे एक ही चाइनीज कंपनी हिकविजन के हैं। इनसे जासूसी का खतरा बताया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि अगर चीन की कंपनी के कैमरे होने की वजह से जासूसी का खतरा है तब तो पूरे देश में इस किस्म का खतरा होगा। भारत में कई संवेदनशील जगहों पर चीन की कंपनियों के कैमरे लगे हैं। सिर्फ कैमरे ही नहीं, बल्कि दूसरे इलेक्ट्रानिक उपकरण भी चीनी कंपनियों के हैं। भारत में तो ज्यादातर लोगों के हाथ में चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन हैं, जिनसे करोडों क्या अरबों तस्वीरें रोज खींची जाती हैं और वीडियो बनाए जाते हैं। अगर चीनी उपकरणों से जासूसी होने का खतरा है तब तो सारे उपकरण बदलने चाहिए। दिल्ली के एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे बदल देने से क्या चीन की जासूसी से छुटकारा मिल जाएगा?

ममता का फिर दिल्ली चलो' का ऐलान

ममता बनर्जी ने एक बार फिर दिल्ली चलो' का ऐलान कर दिया है। वे हर विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का ऐलान करती है। उनकी पार्टी भी इस तरह की घोषणा करती है। पिछले चुनाव में यानी 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने बहुत साफ तरीके से कहा था कि दिल्ली का रास्ता बंगाल से होकर जाएगा। यह भी कहा गया था कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति के लिए कूच करेंगी और 2024 में प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष के एक मजबूत गठबंधन इंडिया' ब्लॉक का गठन हुआ तो ममता बनर्जी ने खुद को उससे अलग कर लिया और बंगाल की राजनीति ही करती रहीं। अब फिर उनके दिल्ली फतह करने की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार उन्होंने खुद ही कहा है कि 2026 में बंगाल जीतने के बाद दिल्ली जीतेंगे। माना जा रहा है कि हर बार बांग्ला मानुष को यह संदेश दिया जाता है कि उनकी नेता ममता बनर्जी देश की नेता बनने लायक हैं और वे जीतीं तो देश की राजनीति करके प्रधानमंत्री भी बन सकती है। गौरतलब है कि आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भागीदारी बंगाल की रही थी लेकिन आज तक वहां का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सका है। यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस बात का ज्यादा प्रचार कराते है कि ममता दिल्ली जाएंगी। वे दिल्ली जाएंगी तभी कोलकाता में मुख्यमंत्री की कुर्सी अभिषेक के लिए खाली होगी।

बुजुर्ग राज्यपालों के लिए राहत की बात

भारत में राज्यपाल बनने के बाद सक्रिय राजनीति में लौटना कोई अनोखी बात नहीं है। कई नेता राज्यपाल रहने के बाद सक्रिय राजनीति में लौटे और मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बने हैं। सुशील कुमार शिंदे से लेकर मोतीलाल वोरा तक की मिसालें हैं। भाजपा ने भी उत्तर प्रदेश में बेबीरानी मौर्य से लेकर तमिलनाडु में तमिलिसाई सौंदर्यराजन तक को चुनाव लड़ाया। लेकिन अगर भाजपा का कोई नेता बुजुर्ग हो और राज्यपाल रहा हो फिर भी उसे चुनाव लड़ने का मौका मिले तो यह भाजपा के कई बुजुर्ग नेताओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी। असल में भाजपा ने एक अघोषित नियम बना रखा है कि 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अपवाद बनाया गया है। लेकिन इस बार भाजपा केरल में पूर्व राज्यपाल के.राजशेखरन को चुनाव लड़ा रही है, जिनकी उम्र 73 साल है। गौरतलब है कि कुम्मनम राजशेखरन मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। वे इस बार अरानमुला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक समय दक्षिण भारत और खास कर केरल की राजनीति में वे भाजपा का चेहरा माने जाते थे। लंबे समय तक संघ प्रचारक और भाजपा के नेता रहे राजशेखरन की कुल संपत्ति एक लाख रुपए की है। बहरहाल, वे राज्यपाल रहे है, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए भाजपा के जो नेता राज्यपाल बनाए गए हैं और जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है, उन्हें चिंता करने की जरुरत नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

आठ साल में पांच भाइयों की मौत- पंजाब में नशे ने एक-एक कर बुझाए घर के सभी चिराग, क्या बोले परिजन?

अमृतसर । नशे की लत के कारण एक ही परिवार के पांच बेटों की मौत हो गई। पांचवें बेटे ने मंगलवार को गुरु नानक देव अस्पताल में आखिरी सांस ली। मृतक का नाम सोनू है और वह कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी का रहने वाला था। उसे सोमवार को इलाज के लिए अमृतसर लाया गया था। सोनू को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इससे पहले सोनू के चार भाइयों की भी नशे की लत के कारण ही मौत हो गई थी। हालांकि युवक की हालत बिगड़ने का पता चलने पर मुख्यमंत्री ने पूरा इलाज सरकारी खर्च पर करवाने की बात कही थी।

आठ वर्षों में पांच भाइयों की मौत

जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले जोगिंदर पाल सिंह उनकी पत्नी मंजीत कौर अपने बेटे सोनू का इलाज करवाने के लिए अमृतसर आए थे। सांस में तकलीफ होने पर सोमवार को पहले कपूरथला के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मगर वहां से अमृतसर रेफर कर दिया था लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सोनू के खिलाफ नशे का केस दर्ज था और वह खुद भी इसका आदि था। वहीं, इससे पहले सोनू के बड़े भाई जसविंदर सिंह की भी नशे के कारण 8 साल पहले जेल हिरासत में मौत हुई। दूसरे भाई बलविंदर की 7 साल पहले मौत हुई। तीसरे भाई रवि की मौत 2021 में हो गई थी। उस पर एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज था। वहीं, चौथे भाई मिथुन की मौत 2023 में हुई जिस पर भी एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज था।

सवालों के घेरे में पुलिस

एक ही परिवार के पांच बेटों की नशे के कारण मौत हो जाने से पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि पुलिस की ओर से दावा किया जाता है कि नशा तस्करों की कमर तोड़ दी है।

जबकि मृतक के परिवार वालों का कहना है कि बड़ी आसानी से नशा बिक रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा। उनके घर पर भी लोग खुद ही नशा देने के लिए आ जाते थे।

जालंधर में बैंक लूट : रिटायर्ड डीएसपी का बेटा गिरफ्तार, दो मिनट में पिस्टल दिखाकर लूटे थे छह लाख रुपये

जालंधर (पंजाब) । जालंधर के खुरला किंगरा के कुक्की ढाब रोड स्थित बैंक एन्क्लेव फेज-2 में सोमवार दोपहर 2:35 बजे दिनदहाड़े बैंक लूट की वारदात पुलिस ने ट्रेस कर ली है। ब्लैक रंग की एक्टिवा पर आए दो नकाबपोश लुटेरों ने मात्र 2 मिनट में 6 लाख 27 हजार 700 रुपये लूट लिए और फरार हो गए। वारदात पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में हुई, जहां उस समय कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। मंगलवार को पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर, डीसीपी इन्वेस्टिगेशन मनप्रीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि लंच के बाद बैंक में कुल 6 लोग मौजूद थे - 3 कर्मचारी और 3 ग्राहक। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक लुटेरा लाल जैकेट में पिस्टल लेकर सीधे कैशियर सीमा के पास पहुंचा और कैश देने की धमकी दी, जबकि दूसरा नीली चेक कमीज में नुकीले हथियार के साथ खड़ा रहा। डर के माहौल में कैशियर ने काउंटर पर रखा सारा कैश सौंप दिया। लुटेरों ने कैरी बैग में रकम भरी और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी सिमरनजीत सिंह उर्फ अमरीक सिंह निवासी ग्रीन मॉडल टाउन जालंधर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक रिवाल्वर और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए। जांच में सामने आया कि पकड़ा गया आरोपी एक रिटायर्ड डीएसपी का बेटा है, जो नशे का आदी बताया जा रहा है। यही वारदात का मास्टरमाइंड है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने बैंक की रेकी की थी और उसे पता था कि दोपहर बाद बैंक में भीड़ कम होती है और गार्ड तैनात नहीं रहता। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल को लाइसेंसी हथियार बताया जा रहा है।

लुटेरे वारदात के बाद कुक्की ढाब से होते हुए लांबड़ा और खांबड़ा की ओर निकले, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और हुलिए के आधार पर अर्बन एस्टेट एरिया तक उनका रूट ट्रेस कर लिया। कपड़े बदलने के बावजूद पुलिस ने दोनों को पहचान लिया। दिनदहाड़े बैंक में गार्ड की गैरमौजूदगी और ग्राहकों को सूचना न देने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना ने बैंक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंतन की जरूरत को उजागर कर दिया है।

उत्तराखंड में संशोधित समान नागरिक संहिता लागू, धोखाधड़ी-बलपूर्वक विवाह पर होगी 7 साल की

देहरादून। प्रदेश में अब कोई व्यक्ति यदि बल, दबाव या धोखाधड़ी कर किसी से विवाह करता है अथवा ऐसा कर किसी के साथ लिव इन में रहता है तो पकड़े जाने पर उसे सख्त सजा होगी।

यह सजा सात साल तक हो सकती है। वहीं, विवाहित व्यक्तियों का बिना संबंध विच्छेद किए दूसरा विवाह करना अथवा लिव इन में रहना भी दंडनीय अपराध होगा। पहले से ही लिव इन में रहने के बावजूद अन्य के साथ लिव इन में रहना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। समान नागरिक संशोधन अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई है। लोक भवन की स्वीकृति के बाद विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने गैरसैंण में हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समान नागरिक संशोधन विधेयक पारित किया था। इसे मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया था। अब इसे लोक भवन में मंजूरी के बाद अधिसूचित कर दिया गया है।

ये हैं प्रमुख प्रविधान

पहले से लिव इन में रहने के बावजूद, दूसरे के साथ लिव इन में रहने पर सात साल की सजा

गलत जानकारी देकर नाबालिग के साथ विवाह करने अथवा लिव इन पर रहने वाले को छह माह की सजा व 50 हजार का जुर्माना

नाबालिग से जुड़े मलों में आरोपित पर पोक्सो के साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत अलग से मुकदमा

बाल विवाह के आरोपित पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई

गैर कानूनी तरीके से विवाह-विच्छेद करने पर तीन साल का कारावास व जुर्माना

विवाह के लिए अपनी पहचान छिपाने व गलत जानकारी देने पर बीएनएस के तहत कार्रवाई।

जीवित पति अथवा पत्नी के रहते, दूसरा विवाह करने पर बीएनएस के अनुसार दंड

नाबालिगों के बीच विवाह व लिव इन पर तथ्य छिपाकर रहने पर बीएनएस के तहत कार्रवाई।

उत्तराखंड में मकान सूचीकरण - प्रदेश को 32 हजार क्षेत्रों में बांटा गया, 10 अप्रैल से शुरू होगा कार्य

देहरादून।

मलिन बस्तियों की गणना अलग से होगी, स्वगणना राज्यपाल-मुख्यमंत्री करेंगे

गलत जानकारी पर जुर्माना, कार्मिकों की लापरवाही पर कारावास का प्रावधान

प्रदेश में जनगणना के तहत पहले चरण में मकान सूचीकरण के लिए प्रदेश को 32 हजार क्षेत्रों में बांटा जाएगा। एक क्षेत्र में 800 अथवा उससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को एक इकाई माना जाएगा। खाली राजस्व ग्रामों को भी एक इकाई के रूप में लिया जाएगा। दो ग्रामों को अलग-अलग इकाई माना जाएगा, भले ही दोनों की जनसंख्या 800 से कम ही क्यों न हो। जिन वार्ड अथवा गांव में आठ सौ से अधिक की जनसंख्या होगी, वहां अधिकतम आठ सौ जनसंख्या को एक ब्लाक माना जाएगा। प्रदेश में मकान सूचीकरण का कार्य 10 अप्रैल से शुरू होना है। इसकी तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। इस समय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए नगरों व तहसीलों को चार्ज के रूप में भी चिह्नित किया जा रहा है। दो लाख की जनसंख्या पर एक चार्ज बनेगा। जिसकी जिम्मेदारी चार्ज अधिकारी की होगी। नगर निकायों में सहायक नगर अधिकारी, पंचायतों में अधिशासी अधिकारी व कैंट बोर्ड में मुख्य अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी चार्ज अधिकारी की भूमिका में रहेंगे। अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्रदेश को 239 चार्ज में बांटा गया है। हर चार्ज को भी क्षेत्रों में बांटा गया है। जहां प्रगणकों की तैनाती की जाएगी। एक प्रगणक अधिकतम अपने क्षेत्र के 800 जनसंख्या वाले क्षेत्र को देखेगा।

मलिन बस्तियों की अलग से होगी गणना

प्रदेश में मलिन बस्तियों की अलग से गणना की जाएगी। ये बस्तियां किसी वार्ड के अंतर्गत हो अथवा गांव के। इन्हें वार्ड या गांव का हिस्सा न मानते हुए, इनकी अलग गणना की जाएगी।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री से भी कराएंगे स्वगणना

प्रदेश में स्वगणना की शुरुआत राज्यपाल व मुख्यमंत्री के हाथों कराई जाएगी। इसके लिए वे विभाग के निर्धारित प्रारूप पर जानकारी साझा करेंगे।

दंड का भी किया गया है प्रविधान

स्वगणना व मकान सूचीकरण के लिए जनगणना निदेशालय द्वारा दंड का प्रविधान भी किया गया है। इसके तहत गलत सूचना देने, सूचना छिपाने अथवा कार्मिकों को सहयोग न करने वालों पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, जो कार्मिक इस कार्य में लापरवाही करेंगे, यह कार्य नहीं करेंगे, सूचनाओं को सार्वजनिक करेंगे अथवा पूरी सूचनाएं नहीं भरेंगे। उन पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि तीन वर्ष तक कारावास भी हो सकता है।

आमजन नहीं कर सकेगा जनगणना अधिकारी की पुस्तक का निरीक्षण

स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जनगणना अधिकारी द्वारा कार्य के दौरान बनाई गई किसी भी पुस्तक, रजिस्टर अथवा रिकार्ड का निरीक्षण नहीं कर सकेगा।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें दर्ज किसी भी प्रविष्टि को नागरिक कार्यवाही या किसी आपराधिक कार्यवाही के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा।

दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण- उत्तराखंड में पीएम मोदी के आगमन की भव्य तैयारियां

देहरादून।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 14 अप्रैल को उत्तराखंड आगमन और उनके हाथों दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दृष्टिगत तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इस क्षण को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताते हुए सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही इस भव्य आयोजन में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी पर जोर दिया, ताकि यह जन उत्सव का रूप ले सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समारोह की रूपरेखा अत्यंत आकर्षक एवं सुव्यवस्थित बनाई जाए। विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भव्यता के साथ आयोजित करने पर बल देते हुए कहा कि गढ़वाली, कुमाऊंनी व जौनसारी लोकगीत-लोकनृत्य से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक इस आयोजन में दिखनी चाहिए। कार्यक्रम स्थल की साज-सज्जा पारंपरिक एवं आधुनिकता के समन्वय से करने और कलाकारों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल सरकारी कार्यक्रम न होकर उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और गौरव का प्रतीक बने, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनमानस से भी इस ऐतिहासिक अवसर में बढ़-चढ़कर सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों से

निकलकर राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल हों और पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए। साथ ही इस कार्यक्रम से पहले प्रदेशभर में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि, प्रशासन और आमजन मिलकर इस आयोजन को स्वच्छ, सुंदर व यादगार बनाएं। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस आर्थिक गलियारे के माध्यम से दिल्ली व देहरादून के बीच यात्रा समय में कमी आने से पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में औद्योगिक, व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार होने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह एक्सप्रेसवे लाजिस्टिक्स, परिवहन व निवेश के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस परियोजना का लोकार्पण राज्य के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा और प्रदेश को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में और अधिक सशक्त बनाएगा। बैठक में राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट, सचिव शैलेश बगौली, मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे, देहरादून के डीएम सविन बंसल, अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम धामी ने तैयारियों की समीक्षा कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर दिया जोर

एक्सप्रेसवे उत्तराखंड के विकास, पर्यटन और रोजगार को देगा नई दिशा

हनुमान जयंती पर जाखू मंदिर में गूंजा जयकारा, अजय माकन ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली।(आकाश शक्य) जयंती के पावन पर्व पर शिमला स्थित विश्वविख्यात श्री हनुमान मंदिर, जाखू में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के कोषाध्यक्ष श्री अजय माकन ने भगवान हनुमान के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर जय श्री राम और बजरंगबली की जय के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच श्री माकन ने देशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हनुमान जी की अटूट भक्ति, अद्भुत शक्ति और निस्वार्थ सेवा भाव हम सभी के जीवन के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने भगवान से देश में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारे की कामना की तथा कहा कि आज के समय में हनुमान जी के आदर्शों–समर्पण, साहस और सेवा–को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर उनके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं श्रद्धालु भी उपस्थित रहे, जिन्होंने भक्ति भाव से पूजा में भाग लिया।

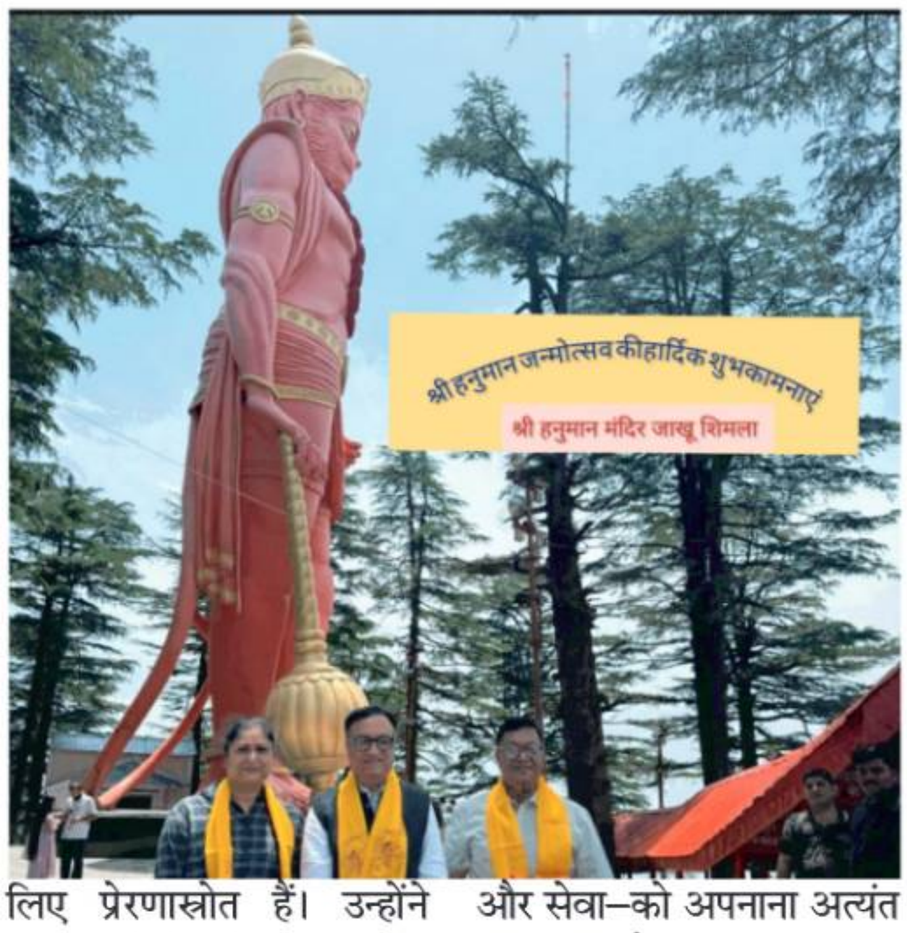

संगठन सृजन अभियान के तहत बाबरपुर जिला बैठक संपन्न

दिल्ली।(इंद्रजीत सिंह) संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत बाबरपुर जिले की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर एआईसीसी ऑब्जर्वर एवं पूर्व सांसद आर.सी. खूंटियां, जिला अध्यक्ष राज कुमार जैन, लक्ष्मण रावत, पूर्व विधायक राजेश लिलोठिया, विपिन शर्मा, भीष्म शर्मा, अब्दुल रहमान, हाजी इशराक, पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश जैन, सुखवीर सिंह, निगम पार्षद हाजी जरीफ, पूर्व पार्षद चौधरी अजीत सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुरेशवती चौहान सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने सुझाव साझा किए और संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंगत राम सिंघल ने कहा, कांग्रेस का संगठन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हम हर कार्यकर्ता को जोड़ते हुए बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। जब संगठन मजबूत होगा, तभी हम जनता की आवाज़ को प्रभावी ढंग से उठा पाएंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ सकेंगे। वक्ताओं ने कहा कि संगठन सृजन अभियान का मुख्य उद्देश्य पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका में लाना है, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस और अधिक मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को उठा सके।बैठक का समापन संगठन को मजबूत बनाने और आपसी समन्वय बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ।

दिल्ली विधानसभा सुरक्षा में चूक - तीस हजारी कोर्ट का आदेश, आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया आरोपी सरबजीत

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा में हुए सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी सरबजीत सिंह को तीस हजारी कोर्ट ने आठ दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। यह फैसला कोर्ट ने पुलिस की उस अर्जी पर सुनाया, जिसमें उन्होंने आरोपी से पूछताछ और मामले की तह तक जाने के लिए और अधिक समय मांगा था। दिल्ली विधानसभा सुरक्षा में चूक मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने अदालत में 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने आरोपी सरबजीत को आठ दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है। बता दें कि देश की राजधानी में सोमवार दोपहर करीब दो बजे दिल्ली विधानसभा परिसर में एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई। एक नकाबपोश व्यक्ति ने कार से लोहे का गेट तोड़ दिया। उसने विधानसभा परिसर में एक जगह गुलदस्ता रखा और फिर चला गया। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। दो अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान सरबजीत सिंह के रूप में हुई है। वह कार चला रहा था।

मणिपुर के बिष्णुपुर में बम धमाका- दो बच्चों की मौत, दो महिलाएं घायल; पांच जिलों में 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद

इंफाल ।

मणिपुर में एक बार फिर हिंसक घटना सामने आई है। मंगलवार देर रात बिष्णुपुर जिले के मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाके में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा किए गए बम हमले में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामले को लेकर मृतक बच्चों के दादा ओइनम बाबूतोम ने बताया कि यह घटना रात करीब एक बजे हुआ। उस समय एक बम सीधे उनके घर पर आकर गिरा। घर के कमरे में उनकी बहू और दो छोटे बच्चे सो रहे थे। धमाका इतना जोरदार था कि पांच साल के मासूम और छह महीने की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चों की मां इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटना के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए मणिपुर सरकार ने इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, थोउबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया है। सरकार के निर्देश के अनुसार यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले तीन दिनों तक जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला एहतियातन लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलने से रोका जा सके।

जातीय हिंसा की चपेट में रहा है मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाका

जिस मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाके में यह हमला हुआ, वह निचले क्षेत्र में आता है और चुराचांदपुर के पहाड़ी इलाकों के काफी करीब है। यह इलाका पहले भी 2023 और 2024 में जातीय हिंसा के दौरान लगातार गोलीबारी और तनाव का केंद्र रहा है।

भाजपा विधायक ने की हमले की निंदा

इस घटना के बाद स्थानीय भाजपा विधायक टीएच शांति सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे बेहद क्रूर और अमानवीय कृत्य बताया। विधायक ने कहा कि यह हमला आतंकवाद से कम नहीं है और समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमले में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इतने छोटे और मासूम बच्चों की इस तरह हत्या होना बेहद दुखद और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र
प्रिय पाठक, विज्ञापन दाता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोट: पूर्व प्रकाशित लेखो को न भेजे।
संपादक: विजय कुमार
अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं।
Account Holder Name ASHOKA EXPRESS

पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे

नई दिल्ली । असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के तीन पासपोर्ट होने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद असम पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. असम पुलिस दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पहुंची. हालांकि वहां कांग्रेस प्रवक्ता नहीं मिले, जिसके बाद वो कुछ सामान अपने साथ लेकर गई है. असम पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, वह कल गुवाहाटी से भाग गए थे. मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि पुलिस उनके दिल्ली स्थित आवास पर गई थी, लेकिन वह हैदराबाद भाग गए हैं. कानून अपना काम करेगा. असम पुलिस की पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और डरे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह उचित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तरह की बदले की कार्रवाई है, एक दबंग जो राय मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ को दबा रहा है, जो उसके कई काले कारनामों को उजागर कर रहा है. जो लोग डराते-धमकाते हैं, वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है. यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को आसन्न हार का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास तीन अलग-अलग पासपोर्ट कैसे हैं? उनको तीन पासपोर्ट रखने की क्या जरूरत है? क्या वे कोई अपराधी हैं?

16500 करोड़ के सरकारी ठेके, बहुजन समाज को कितना हिस्सा? राहुल बोले- सरकार के पास डाटा ही नहीं

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में सार्वजनिक निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकों में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों की हिस्सेदारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास इस बात का कोई डाटा ही नहीं है कि इन वर्गों को कितने ठेके दिए गए। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि उन्होंने पिछले साल दिए गए 16,500 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक निर्माण ठेकों में एससी/एसटी और ह्वष्ट उद्यमियों की भागीदारी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जवाब बेहद चिंताजनक था। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस संबंध में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। दरअसल, राहुल गांधी ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 6264 के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से पिछले पांच वर्षों में दिए गए ठेकों की

संख्या और कुल मूल्य की जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा था कि इनमें से कितने ठेके एससी/एसटी और ओबीसी स्वामित्व वाले व्यवसायों को दिए गए और क्या सरकार ने एससी/एसटी उद्यमों के लिए तय चार प्रतिशत लक्ष्य को पूरा किया है। उन्होंने ओबीसी उद्यमियों के लिए भी ऐसे लक्ष्य तय करने की योजना पर सवाल उठाया। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राय मंत्री तोखन साहू ने बताया कि कुल ठेकों का डेटा तो उपलब्ध है, लेकिन एससी/एसटी और ओबीसी स्वामित्व वाले व्यवसायों को दिए गए ठेकों का कोई अलग ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्माण ठेकों के लिए ऐसी ट्रैकिंग अनिवार्य नहीं है। राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नीति के मुताबिक लघु व मध्यम उद्यमों से कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद होनी चाहिए, जिसमें SC/ST स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए 4 प्रतिशत का प्रावधान है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे बड़े और लाभदायक सार्वजनिक निर्माण ठेकों में इस नीति को लागू नहीं किया जाता। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बताया जो जानबूझकर सामाजिक और आर्थिक न्याय को कमजोर करता है। संसदीय आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण ठेकों की संख्या और उनका मूल्य लगातार बढ़ा है। सिर्फ 2025-26 में ही 8,402 ठेके दिए गए, जिनकी कुल कीमत 16,587 करोड़ रुपये रही।

रविशंकर प्रसाद बोले- क्या मर्यादा भूली कांग्रेस, गुजरात का अपमान क्यों? खरगे के बयान पर किया पलटवार

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खरगे के कथित गुजरात के लोगों को अनपढ़ बताने वाले बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को शोभा नहीं देती। भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने इस टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया और कांग्रेस अध्यक्ष से सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह मर्यादा भूल चुका है? प्रसाद ने सवाल उठाया कि क्या किसी राय के लोगों को इस तरह संबोधित करना उचित है। उन्होंने कहा क्या महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई और विक्रम साराभाई जैसे महान व्यक्तित्व भी अनपढ़ थे? भाजपा सांसद ने आगे कहा कि गुजरात की साक्षरता दर लगभग 82 प्रतिशत है और इसमें पिछले वर्षों में सुधार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राजनीतिक विरोध के चलते कांग्रेस इस तरह के बयान दे रही है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख बताने की मांग की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सलाह दी कि वे इस बयान से खुद को अलग करें और पार्टी अध्यक्ष से माफी दिलवाएं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खरगे के अन्य बयान, जिनमें भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) पर की गई टिप्पणियां शामिल हैं, समाज में तनाव बढ़ाने वाली हैं। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केरल में एक बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे गुजरात या अन्य जगहों के अनपढ़ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल में ऐसा संभव नहीं है।

दिल्ली में शुरू हुआ 12वां इंडिया रबर एक्सपो 2026, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित 12वें इंडिया रबर एक्सपो 2026 के उद्घाटन किया। इस चार दिन की प्रदर्शनी में देश-विदेश से कई प्रतिनिधियों आए। इस महाकुंभ को एशिया की सबसे बड़ी रबर प्रदर्शनी माना जा रहा है, जो भारतीय रबर क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी. IRE 2026 केवल घरेलू नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय मंच है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों ने भारत को एक सशक्त विनिर्माण राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है. उन्होंने बताया कि रबर उद्योग इस बढ़ती औद्योगिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर रहा है.मुख्यमंत्री ने कहा, रबर उद्योग को देश की औद्योगिक प्रगति का एक अपरिहार्य स्तंभ बताया, जो ऑटोमोबाइल से लेकर एयरोस्पेस और घरेलू उत्पादों तक अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहा है. उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से उद्योगों को नई ऊर्जा मिली है, जिससे भारत अब गुणवत्ता और तकनीक के मामले में दुनिया का मुकाबला कर रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा, भारत अपने सिविल न्यूक्लियर कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है. यह कदम न केवल हमारी वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है. मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, केंद्र सरकार के सतत प्रयासों से उद्योगों को नई गति मिली है और दिल्ली सरकार निवेश, नवाचार और उद्योग-अनुकूल वातावरण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने उद्यमियों को दिल्ली में नई तकनीकों और स्टार्टअप्स के माध्यम से रबर क्षेत्र में मूल्य संवर्धन करने के लिए आमंत्रित किया.

आबकारी नीति मामला- अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने उठाया ये कदम, 13 अप्रैल को सुनवाई

नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी नीति मामला में अरविंद केजरीवाल के बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को केस से हटाने की मांग की. दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार (13 अप्रैल) को मामले की सुनवाई करेगा. इससे पहले सोमवार (6 अप्रैल) को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे. इस दौरान उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को आबकारी नीति मामले में उन्हें और अन्य सभी आरोपियों को आरोप मुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से अलग किए जाने का आग्रह किया. हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के अलावा आप के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर और अरुण रामचंद्र पिल्लई सहित अन्य प्रतिवादियों ने भी जस्टिस शर्मा को सुनवाई से अलग

किए जाने के आग्रह के साथ आवेदन दाखिल किए. अदालत ने केजरीवाल और अन्य प्रतिवादियों को सीआईआई की मुख्य याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 अप्रैल तक का समय अंतिम अवसर के तौर पर दिया है. सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे. उन्होंने दलील दी कि कोर्ट कोई नौटंकी का मंच नहीं है और अगर केजरीवाल मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने वकील को हटा देना चाहिए. यह पहली बार नहीं है, जब केजरीवाल ने अदालती कार्यवाही में खुद दलीलें पेश की हों. उन्होंने आगे कहा, इस देश में कुछ लोग हर किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाना अपना पेशा बना लेते हैं. इसे गंभीरता से लेना होगा. यह संस्था के खिलाफ आरोप है और हमें उस संस्था का समर्थन करना होगा. मेहता ने हाई कोर्ट को बताया कि आरोपमुक्त किए गए सात आरोपियों ने एक सुनियोजित योजना के तहत जस्टिस शर्मा को इस मामले की सुनवाई से अलग करने के अनुरोध को लेकर अदालत का रुख किया है.

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा पर सवाल, स्पीकर करेंगे समीक्षा बैठक; पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी रहेंगे मौजूद

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में चूक मामले में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जल्द सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, दिल्ली सरकार के अधिकारियों सहित विभिन्न एजेंसियों को बैठक में शामिल किया जाएगा। विधानसभा की सुरक्षा को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। सूत्र ने कहा कि विधानसभा के सभी चारों गेटों पर मजबूती बढ़ाने के साथ साथ खासकर गेट नंबर- दो को और मजबूत किया जाएगा। यह वही गेट है जहां से सोमवार को एक व्यक्ति गेट को तोड़कर अवैध रूप से विधानसभा में घुस गया था। वहीं विधानसभा के मेट्रो स्टेशन वाली सड़क की तरफ वाली चारदीवारी को भी ऊपर तक कवर किए जाने पर विचार किया जा सकता है। विधानसभा परिसर की यह चारदीवारी पूरी तरह से खुली हुई है जिसमें सड़क के फुटपाथ पर खड़े होकर विधानसभा परिसर के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है जो सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। यहां बता दें कि पिछले कुछ माह से दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ने

की धमकियां ईमेल से मिल रही हैं। यहां तक कि बजट सत्र शुरू होने वाले दिन 23 मार्च और उसके बाद 24 मार्च फिर 25 मार्च को लगातार दिल्ली विधानसभा के ईमेल पर और विधानसभा अध्यक्ष के ईमेल आइडी पर भी धमकी भरे मेल प्राप्त हुए थे। जिसमें कहा जा रहा था कि विधानसभा को बम से उड़ा दिया जाएगा। विधानसभा द्वारा इसकी सूचना दी गई, मगर सुरक्षा जांच में में ऐसा कुछ नहीं मिला था। उसके बाद से लगातार यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। मगर अब सोमवार को जिस तरीके से एक व्यक्ति द्वारा कार के साथ गेट तोड़कर अंदर प्रवेश करने की घटना हुई है। इससे सुरक्षा को लेकर और माहौल गर्मा गया है। विधानसभा में 44 सुरक्षाकर्मी तैनात है जिसमें 21 सीआरपीएफ के जवान हैं बाकी दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं। इस सब के बाद भी इस तरीके की घटना हो जाना और अवैध रूप से घुसे व्यक्ति के 6 मिनट तक विधानसभा परिसर में रहना, यह बताता है कि सुरक्षा में कहीं-कहीं कमी जरूर है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के लोगों से चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि सभी गेटों पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और प्रबंध किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रवासी मजदूरों को राहत- सरकार ने दोगुना किया पांच किलो वाले एलपीजी सिलिंडर का कोटा, बुकिंग के नियम बदले

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने देश भर के विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूरों को एक बड़ी राहत देते हुए 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) गैस सिलिंडरों का दैनिक आवंटन (कोटा) दोगुना करने का फैसला किया है। मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बीच सरकार यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय के इस अहम नीतिगत फैसले से शहरों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को सीधा फायदा मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सिलिंडर का यह बढ़ा हुआ आवंटन प्रवासी श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली औसत दैनिक आपूर्ति पर आधारित होगा। यह संशोधित नया आवंटन सरकार द्वारा मार्च में घोषित की गई 20 प्रतिशत की पिछली सीमा के पार चला गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये अतिरिक्त पांच किलो वाले एफटीएल सिलिंडर सीधे राज्य सरकारों और उनके खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभागों को सौंपे जाएंगे। इन सिलेंडरों का वितरण तेल विपणन कंपनियों की सहायता से विशेष रूप से केवल प्रवासी मजदूरों के लिए ही किया जाएगा, ताकि लक्षित वर्ग तक इसका लाभ पहुंच सके। एलपीजी की मांग को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सरकार ने मांग और आपूर्ति से जुड़े कई कड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं रिफाइनरी आउटपुट- मांग पूरी करने के लिए रिफाइनरियों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। बुकिंग अंतराल में बदलाव- गैस बुकिंग का समय बढ़ाकर शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक कर दिया गया है। वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था- एलपीजी पर से दबाव कम करने के लिए मिट्टी का तेल और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों को भी उपलब्ध कराया गया है। पीएनजी का विस्तार- सभी राज्यों को पीएनजी कनेक्शन का नेटवर्क तेज गति से विस्तारित करने की सलाह दी गई है।

सरकार ने साफ किया है कि इन सबके बीच घरेलू एलपीजी और पीएनजी आपूर्ति के साथ-साथ अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे अति-महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा और आपूर्ति का हाल

सरकार ने आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे एलपीजी बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का ही उपयोग करें और जब तक बहुत जरूरी न हो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचें। साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वे घबराहट में जरूरत से ज्यादा खरीदारी न करें और सूचनाओं के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। प्रवासी श्रमिकों को आश्वस्त करते हुए सरकार ने कहा है कि उनकी एलपीजी आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं है। ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हाल ही में लगभग 51 लाख घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की डिलीवरी की गई है। इस दौरान ऑनलाइन बुकिंग का आंकड़ा उछलकर 95 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके अलावा, गैस की कालाबाजारी या हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन-आधारित वितरण प्रणाली का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

रानी कपूर ने प्रिया कपूर को पद से हटाया, कानूनी कार्रवाई करने की दी कड़ी चेतावनी

नई दिल्ली ।

दिवंगत संजय कपूर से जुड़े विवाद में आरके फैमिली ट्रस्ट पर नियंत्रण को लेकर चल रहा पारिवारिक और कानूनी विवाद अब और गहरा गया है। सोना कॉमस्टार के दिवंगत चेयरमैन संजय कपूर की बुजुर्ग मां रानी कपूर ने प्रिया कपूर को एक नया सीज-एंड-डेसिस्ट (काम रोकने का) नोटिस जारी किया है। 6 अप्रैल को जारी इस सूचना में रानी कपूर ने साफ किया है कि प्रिया कपूर अब ट्रस्टी के पद पर नहीं हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से इस हैसियत से काम करना बंद कर देना चाहिए। यह नया पत्र 21 मार्च को भेजे गए एक पूर्व नोटिस के बाद उठाया गया कदम है। इस नोटिस में रानी कपूर ने 26 अक्टूबर, 2017 के ट्रस्ट डीड के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए प्रिया कपूर को हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। 15 दिनों का नोटिस पीरियड समाप्त होने के बाद, 6 अप्रैल से प्रिया कपूर का ट्रस्टी बने रहना अवैध हो गया है। रानी कपूर ने अपने फैसले के समर्थन में ट्रस्ट डीड के क्लॉज 8.12(i) का विशेष रूप से हवाला दिया है। उनका दावा है कि यह क्लॉज उन्हें बिना कोई कारण बताए किसी भी ट्रस्टी को हटाने की शक्ति

देता है, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रिया कपूर को हटाना पूरी तरह से वैध और बाध्यकारी है। इस विवाद में दोनों ओर से कार्रवाई की गई है, लेकिन रानी कपूर ने प्रिया कपूर के उन पत्रों (24 मार्च और 4 अप्रैल, 2026) को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, जिनमें प्रिया ने रानी कपूर को ही ट्रस्टी पद से हटाने का प्रयास किया था। रानी कपूर के अनुसार, प्रिया की ये कार्रवाइयां कानूनी रूप से अस्थिर हैं और ट्रस्ट में उनके (रानी कपूर के) अधिकार या स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा, प्रिया कपूर के इस दावे को भी खारिज कर दिया गया है कि रानी कपूर ट्रस्टी के रूप में काम करने में असमर्थ हैं। रानी कपूर ने स्पष्ट किया है कि अदालत (न्यायिक हस्तक्षेप) का दरवाजा खटखटाने को अक्षमता नहीं माना जा सकता, बल्कि यह लाभार्थियों के हितों की रक्षा करने के उनके कर्तव्य का एक हिस्सा है। इस पूरे विवाद की जड़ें ट्रस्ट के अस्तित्व और संपत्तियों के अधिकार से जुड़ी हैं। वर्तमान में यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है

ट्रस्ट को चुनौती- रानी कपूर ने अदालत में ट्रस्ट के निर्माण, इसमें संपत्तियों के हस्तांतरण और इसके प्रशासन को सीधे तौर पर चुनौती दी है।

संपत्ति का विवाद - उनका आरोप है कि ट्रस्ट में वे संपत्तियां रखी गई हैं जो कानूनी तौर पर उनकी हैं।

बेदखल करने का प्रयास- रानी कपूर का दावा है कि जून 2025 में उनके बेटे संजय कपूर के निधन के बाद, उन्हें उनकी ही संपत्ति से बेदखल करने की साजिश के तहत इस ट्रस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है।

रानी कपूर ने प्रिया कपूर को किस बात की चेतावनी दी?

रानी कपूर के नोटिस में यह भी बताया गया है कि फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ट्रस्ट के कामकाज पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने प्रिया कपूर की कार्रवाइयों में प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर करते हुए कहा कि किसी भी ट्रस्टी को हटाने के लिए बाकी सभी ट्रस्टियों की मंजूरी जरूरी होती है, जो प्रिया ने नहीं ली। रानी कपूर ने सख्त चेतावनी दी है कि पद से हटाए जाने के बाद प्रिया कपूर द्वारा ट्रस्टी के रूप में लिया गया कोई भी फैसला अनधिकृत माना जाएगा और इसके लिए उन्हें नागरिक और आपराधिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने प्रिया से आरके फैमिली ट्रस्ट से जुड़े सभी दस्तावेज, रिकॉर्ड और सामग्री तुरंत सौंपने की मांग की है। चूंकि मामला अभी अदालत में लंबित है, इसलिए ट्रस्ट और उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण का यह विवाद लगातार तेज होता जा रहा है।

दलाल स्ट्रीट में गिरावट के बीच सर्राफा बाजार का हाल कैसा, आज सोना-चांदी की दरें क्या?

बिजनेस डेस्क । मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज खोलने की धमकी दी, इसके बाद बाजार में घबराहट बढ़ गई। निवेशकों के सतर्क रुख के कारण, मई 2026 के लिए एमसीएक्स चांदी वायदा 1,579 रुपये गिर गया। यह 0.7 फीसदी की गिरावट के साथ 2.31 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। जून 2026 के लिए सोने का वायदा भी 356 रुपये कम हुआ। सोना 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ 1.49

लाख रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। बाजार की स्थिति अस्थिर बनी हुई है। मंगलवार को वैश्विक सोने की कीमतों में मिश्रित रुझान देखा गया। स्पॉट गोल्ड 4,646.69 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर रहा। वहीं, जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 0.2 फीसदी गिरकर 4,674.40 डॉलर पर आ गया। सर्राफा बाजार के जानकारों का अनुमान है कि सोने की कीमतों में हालिया गिरावट को देखते हुए खरीदार अप्रैल से जुलाई वाले शादी के सीजन के लिए गहनों की खरीदारी की पहल कर सकते हैं। अनुमान के मुताबिक अक्षय तृतीया के आसपास कई लोग अग्रिम ऑर्डर दे सकते हैं।

अमेरिका-ईरान तनाव- ट्रंप की चेतावनी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल, एमसीएक्स पर क्रूड रिकॉर्ड हाई पर

नई दिल्ली । अमेरिका और ईरान के बीच गहराते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई मंगलवार की समयसीमा (डेडलाइन) के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई है। इस तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य को ईरान के लिए फिर से खोलने की समयसीमा के सीधे असर से मंगलवार को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 3 प्रतिशत से अधिक का भारी उछाल दर्ज किया गया, जिससे कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। एमसीएक्स पर भी क्रूड 300 रुपये बढ़कर 10,888 रुपये प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि

कच्चे तेल के बाजार में दर्ज किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 3 प्रतिशत या 4.15 डॉलर से अधिक बढ़कर 116.56 डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं, सुबह 9:57 बजे तक ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.69 प्रतिशत या 1.86 डॉलर की बढ़त के साथ 111.63 डॉलर के इंट्राडे उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा था। ब्रेंट क्रूड ने इस संघर्ष की शुरुआत के बाद से 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, जो 27 फरवरी के 72.48 डॉलर के स्तर से उछलकर 9 मार्च तक 119.50 डॉलर तक पहुंच गया था। मंगलवार को वायदा कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें 300 रुपये बढ़कर 10,888 रुपये प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। यह वृद्धि लगातार आपूर्ति संबंधी चिंताओं और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बीच मजबूत वैश्विक ऊर्जा मानकों के अनुरूप रही।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, अप्रैल डिलीवरी के लिए कच्चे तेल की कीमत में 300 रुपये या 2.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 10,888 रुपये प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईइसी तरह, मई अनुबंध में भी 170 रुपये या 1.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह एमसीएक्स पर 9,485 रुपये प्रति बैरल के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। कीमतों में यह ताजा तेजी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के संबंध में ईरान के प्रति दिखाए गए नए आक्रामक रुख के बाद आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि तेहरान जलडमरूमध्य को खोलने की मंगलवार रात की समयसीमा का अनुपालन नहीं करता है, तो उस पर कहर बरपाया जाएगा। उन्होंने यह भी धमकी दी कि ईरान को ÷एक ही रात में खत्म÷ किया जा सकता है। ट्रंप के अनुसार, यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो ईरान का हर पुल नष्ट कर दिया जाएगा और वहां के हर बिजली संयंत्र को हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाएगा।

ऊर्जा आपूर्ति श्रृखला और ईरान की प्रतिक्रिया

दूसरी ओर, ऐसी खबरें हैं कि ईरान ने संघर्षविराम योजना को खारिज कर दिया है और दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी है। वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य का सामरिक महत्व बहुत अधिक है यह जलमार्ग दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के वैश्विक तेल प्रवाह को संभालता है। 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग लगातार बाधित है। इस गतिरोध के कारण इस साल कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो औसतन 100 डॉलर के आंकड़े के आसपास बनी हुई है। ऊर्जा बाजार की इस अस्थिरता का मिला-जुला असर वैश्विक इक्विटी बाजारों पर दिखाई दे रहा है। जहां अमेरिका में वॉल स्ट्रीट मामूली सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ और एशियाई शेयरों में मिला-जुला कारोबार देखा गया, वहीं भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट का रुख रहा। भारत के प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, 1 प्रतिशत तक गिरकर कारोबार कर रहे थे।

दो बाइकों की टक्कर में युवक-युवती गंभीर रूप से घायल

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। थाना क्षेत्र के ढोरही फार्म के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि विगू पुत्री गुंजा किताब खरीदने जा रही थी, तभी खड्डा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बाइक चालक, जो नवतार जंगल का निवासी बताया जा रहा है, वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी उंगली टूट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। युवती का इलाज जिला अस्पताल में, जबकि युवक का निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ताबड़तोड़ घटनाओं से दहला कप्तानगंज, दिनदहाड़े लूट और रात में फायरिंग से फैली दहशत

कप्तानगंज, कुशीनगर।

नगर कप्तानगंज में सोमवार को एक ही दिन हुई तीन बड़ी घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। नगर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन घटनाओं से भय और दहशत का माहौल है। सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे सुभाष चौक स्थित गांधी गली में दिनदहाड़े एक महिला से झपट्टा मारकर एक लाख रुपये लूट लिए गए। खैरटवा निवासी संजीत गुप्ता, पत्नी रघुपति गुप्ता, पास के स्टेट बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रही थीं, तभी बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। यह क्षेत्र घनी आबादी और भीड़भाड़ वाला है, ऐसे में घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। इस घटना के करीब छह घंटे बाद रात लगभग 11 बजे वार्ड संख्या तीन स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल की गली में बाइक सवार तीन बदमाशों ने वार्ड सदस्य मोहम्मद आरिफ के घर पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। दरवाजा नहीं खुलने पर बदमाशों ने अवैध असलहे से तीन राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी और मौके से फरार हो गए। इसके तुरंत बाद करीब 11:10 बजे सच्चिदानंद कॉलेज रोड पर समाजसेवी विक्की मद्धेशिया के घर के पास भी बदमाशों ने पहुंचकर गाली-गलौज और धमकी देते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। लगातार हुई इन घटनाओं से पूरा इलाका थर्रा गया। हालांकि, संयोगवश दोनों ही मामलों में किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पीड़ितों और स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। मोहम्मद आरिफ ने उसी रात और विक्की मद्धेशिया ने मंगलवार दोपहर पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने और जांच की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी क्षेत्र में दुबौली माता मंदिर से जेवर चोरी, मंगल बाजार में फायरिंग, बभनौली और चांदनी चौक जनता मार्केट में वारदात जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

भीषण अग्निकांड में पांच परिवारों के घर राख, बेटी की शादी से पहले उजड़ा आशियाना

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। जनपद के खड्डा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा धनौजी में मंगलवार देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें पांच परिवारों के घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि अकलू, संगीता देवी, संतोष, हरीलाल और गयासु के आशियाने देखते ही देखते खाक हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। आग की चपेट में आकर घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन और अन्य जरूरी सामान जलकर नष्ट हो गया। इस अग्निकांड में अकलू का परिवार सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। उनकी बेटी प्रीति की शादी 15 अप्रैल को तय थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन आग ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया। घर में रखे जेवर, कपड़े, बर्तन और करीब 60 हजार रुपये नकद जलकर खाक हो गए। अब परिवार के सामने बेटी की शादी को लेकर गंभीर चिंता खड़ी हो गई है। वहीं

संगीता देवी की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। उनके तीन छोटे बच्चे हैं और पति पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। मजदूरी कर बच्चों का पालन-पोषण करने वाली संगीता अब पूरी तरह बेघर हो गई हैं और उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। आग से प्रभावित सभी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वे अपने जले हुए घरों के पास बैठकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की आस लगाए हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत एवं मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि पीड़ित परिवारों को दोबारा बसाया जा सके और प्रीति की शादी जैसी जरूरी जिम्मेदारियां पूरी हो सकें।

भूमि की फर्जी दस्तावेज पर वसीयत कराकर बेचने का प्रयास

पीड़ित बुजुर्ग एसडीएम से शिकायत कर न्याय की लगाई गुहार

महराजगंज।

निचलौल क्षेत्र के गांव छितौना निवासी एक व्यक्ति की भूमि को एक शख्स ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर वसीयत करा ली। उसके बाद शख्स उक्त भूमि को बेचने के प्रयास में जुट गया है। मामले की जानकारी होने पर भूमि के मालिक पीड़ित व्यक्ति मंगलवार को तहसील पहुंच एसडीएम के सामने फफक पड़ा। उसके बाद पीड़ित एसडीएम के पूछताछ में पूरी बात बताने के साथ ही शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। छितौना निवासी राजेंद्र ने बताया है कि वह दलित समुदाय के रामहरख और बलासी से आराजी संख्या 381 रकवा 0.291 हेक्टेयर भूमि बैनामा लिए है। पीड़ित का आरोप है कि पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से उक्त भूमि का वसीयत करा ली है। हालांकि उक्त व्यक्ति सामान्य समुदाय से आता है। इतना ही उक्त विवादित भूमि का मुकदमा उपजिलाधिकारी न्यायिक, उपजिलाधिकारी के साथ ही सिविल जज (अवर खंड) महराजगंज और अनुसूचित न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद भी शख्स उक्त विवादित भूमि को बेचने के फिराक है। ऐसे में मामले की जांच कर भूमि को बेचने से रोकने के साथ ही शख्स पर कानूनी कार्रवाई की जाय। वही एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है। उक्त भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

गैस नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं ने तहसील पहुंच किया हंगामा

निचलौल।

क्षेत्र स्थित एक गैस एजेंसी पर गैस नहीं मिलने से परेशान उपभोक्ता मंगलवार को आक्रोशित हो उठे। उसके बाद आक्रोशित उपभोक्ता गोलबंद होकर गैस एजेंसी से तहसील परिसर जा पहुंचे। जहां पर उपभोक्ता गैस एजेंसी के कर्मियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए हंगामा करने लगे। इसी बीच उपभोक्ताओं की हंगामा की आवाज सुन मौके पर तहसीलदार आ पहुंचे। तहसीलदार के काफी प्रयास करने और आश्वासन के बाद उपभोक्ता किसी तरह शांत हुए। उसके बाद तहसील के कर्मियों ने किसी तरह राहत की सांस ली। तहसील पर हंगामा कर रहे उपभोक्ता

तहसीलदार के आश्वासन पर शांत हुए आक्रोशित उपभोक्ता

अनिल, गुड्डू, राजेश, सुनीता आदि ने बताया कि वह लोग करीब एक महीने से गैस के लिए एजेंसी का चक्कर लगा रहे है। लेकिन एजेंसी के कर्मियों की मनमानी के चलते उन्हें गैस नहीं मिल पा रहा है। हद तो तब हो गई जब वह लोग गैस के लिए बुकिंग करने के बाद रकम भी जमा कर दिए। उसके बाद भी गैस एजेंसी से उन लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बुकिंग गैस मोबाइल पर मैसेज के जरिए कई दिन पहले ही डिलेवरी दिखाया जा रहा है। वही गैस के एक कर्मी ने बातचीत में बताया कि एजेंसी कर हर रोज गैस आ रहीं है। जिसे नियम के मुताबिक उपभोक्ताओं में वितरण भी किया जा रहा है। एजेंसी पर उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक होने के चलते थोड़ी दिक्कत हो रही है। जिसे लगातार सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। वही तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने बताया कि आक्रोशित उपभोक्ताओं से उनकी समस्याओं को सुनने के बाद जल्द निस्तारण के लिए गैस एजेंसी के कर्मियों से वार्ता की गई। उसके बाद तहसील कर पहुंचे सभी उपभोक्ताओं को गैस वितरण के लिए सूची तैयार कर गैस देने के लिए निर्देशित किया गया है।

166 करोड़ की लागत से बदलेगी देवरिया बस स्टेशन की सूरत, पीपीपी मॉडल पर बनेगा प्रदेश का चौथा सबसे भव्य टर्मिनल

जर्जर भवन और जलभराव से मिलेगी मुक्ति – तीन लाख वर्गफुट में सिनेमाघर, मॉल और होटल जैसी सुविधाओं से लैस होगा नया परिसर

कैबिनेट की मुहर – प्रशासनिक अड़चनों को पार कर धरातल पर उतरेगी योजना, जल्द शुरू होगी टेंडर की

विधायक शलभ मणि की पैरवी लाई रंग, कैबिनेट ने दी मंजूरी

देवरिया। जनपद के लाखों यात्रियों के लिए वह इंतज़ार खत्म होने वाला है, जो वर्षों से एक अदद आधुनिक बस स्टेशन की बाट जोह रहे थे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में देवरिया में 166 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक और भव्य बस स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है।पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित यह प्रोजेक्ट न केवल जनपद की परिवहन व्यवस्था को सुधारेगा, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे को भी एक नई पहचान देगा। खास बात यह है कि आवंटित बजट और भव्यता के मामले में यह प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा बस स्टेशन होगा, जो लखनऊ, देवीपाटन और सोनौली जैसे बड़े टर्मिनल्स को टक्कर देगा। जिसकी लागत 166 करोड़ रुपये आंकी गई है। वर्तमान में देवरिया का बस स्टेशन अपनी बदहाली के लिए सुर्खियों में रहता है। टूटी सड़कें, बरसात में जलभराव और बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के पीछे देवरिया सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की लंबी और कठिन राजनीतिक लड़ाई रही है। विधायक बनने के बाद से ही शलभ मणि त्रिपाठी इस बस स्टेशन की बदहाली को लेकर मुखर रहे। उन्होंने न केवल हर विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, बल्कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत भेंट कर जनपद की इस जरूरत को विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा। कई बार प्रशासनिक और विभागीय अड़चनें आईं, जमीन को लेकर भी पेंच फंसा, लेकिन विधायक की जिद थी कि देवरिया को एक ऐसा बस स्टेशन मिले जो जिले की नई पहचान बने। पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर बनने वाला यह बस स्टेशन करीब तीन लाख वर्गफुट के विशाल क्षेत्र में फैला होगा। इसे केवल एक बस अड्डे के तौर पर नहीं, बल्कि एक आधुनिक कमर्शियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ यात्रियों को बस पकड़ने के साथ-साथ शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, होटल और बेहतरीन रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। पहले इस स्टेशन को शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना थी, लेकिन विधायक और प्रशासन के आपसी समन्वय के बाद अब यह शहर के भीतर ही अपनी पुरानी जगह पर भव्य रूप लेगा। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद अब विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।

संगठन सृजन में महराजगंज अव्वल, जिला अध्यक्ष और उनकी टीम बधाई की हकदार - सत्य नरायन पटेल

महराजगंज।

मंगलवार को कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की समापन समीक्षा समारोह में अपने विचार रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा कि यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि संगठन सृजन अभियान में महराजगंज जनपद सभी 75 जिलों में शीर्ष स्थान पर है। यह जिले के कांग्रेस संगठन खासकर अध्यक्ष विजय सिंह और उनकी टीम इसके लिए बधाई का हकदार है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी जिले में कांग्रेस का संगठन था, पदाधिकारी भी थे लेकिन इतना शानदार सांगठनिक प्रदर्शन किसी का नहीं था। वैश्विक परिदृश्य पर अपना विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि आज देश की हालत ठीक नहीं है पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कमी से जनता परेशान है। पंडित नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन एवं विदेश नीति से अलग होने के कारण विश्व में भारत की साख गिर रही है। उन्होंने मौजूदा पांच प्रदेशों के विधानसभा चुनाव पर कहा कि राहुल,प्रियंका एवं खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस किसानों, नौजवानों एवं मजलूमों की लड़ाई जोरदार ढंग से लड़ रही है। भाजपा से जनता का मोह भंग हो चुका है। आगामी पांचों प्रदेशों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार सुनिश्चित लग रही है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता के रहे जिलाध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे की राजनीति करती है। संगठन के माध्यम से भाजपा के झूठ एवं कांग्रेस के नीतियों की जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस के नि. प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद एवं पूर्व प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्रा ने कहा कि 2027 में भाजपा की सत्ता जा रही है क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और 2014 से कभी आधार कार्ड की लाइन में कभी राशन और खाद की लाइन में और अब गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के लाइन में लगा के देश को भ्रमित कर रखा है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर राम नारायण चौरसिया ने किया। पूर्व जिलाध्यक्ष झिनकू चौधरी,शरद कुमार सिंह बबलू एवं विपिन पाल ने कहा कि महराजगंज का संगठन आज कार्यकर्ताओं के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अग्रणीय संगठन बन गया है। 2027 में इसी संगठन के बल पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में परास्त करना है। संगठन समीक्षा समारोह को अन्य के अतिरिक्त मुख्य रूप से पूर्व प्रत्याशी सदामोहन उपाध्याय, कपिल देव शुक्ला,विनोद सिंह,विधि नारायण वर्मा,राजू गुप्ता, यंत्री प्रसाद मौर्य,गोपाल शाही ने भी संबोधित किया।

माननीय प्रधानमंत्री-भारत सरकार, श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री, श्रीमती रेखा गुप्ता जी

पूर्व केजरीवाल सरकार का कमाऊ पूत

सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के

अधिशासी अभियंताओं द्वारा 11 वर्षों से विकास एवं निर्माण कार्य में बेहद घटिया निर्माण सामग्री व फर्जी बिल लगाकर।

करोड़ो के घोटाले व भष्टाचार की जांच

श्रीमान निदेशक, सीबीआई, भारत सरकार से कराई जाएं।

छठ घाटो में टेन्ट, पानी टैंकर, बड़े नालो की साफ-सफाई, बॉउन्ड्रीवाल के

फर्जी बिल लगाकरकिए गए करोड़ो के घोटाले और हरे-भरे पेड़ो को काटकर खुलेआम बेचा जा रहा है।

I&FC के श्री अशोक कुमार-(FC-III), ए.सुरेन कुमार (पीएनडी), विवेक चौहान (CD-II), शोभित जैन (CD-III), सोमनाथ कश्यप (CD-IV), बी.बी.नागपाल (CD-V), प्रदीप नैक (CD-VII), पुनित डुडेजा (CD-IX), प्रशांत मिश्रा (CD-X), विवेक चौहान (CD-XI), ए.सुरेन कुमार (CD-XII), अनुराग जैन (CD-XIII), एई, जे.ई ने ठेकेदारों की मिलीभगत से दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों के विकास एवं निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री और फर्जी बिल बनाकर कर रहे है अपना समाजवाद दूर!

भ्रष्टाचारियों व कमिशन खोरो का अड्डा बना

श्री सुधीर कुमार आर्य, ई.ई, सतर्कता कार्यालय: बसई दारापुर?

निवेदक: अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा (विज्ञापन)